तिब्बत देश

भारत–चीन रिश्ते में नकलीपन के खतर

चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा को लेकर उम्मीदें की जा रही हैं कि इसके बाद भारत–चीन संबंध इतने मीठे हो जाएंगे कि हम फिर से हिंदी–चीनी भाई–भाई हो जाएंगे। भारत में चीन के पैरोकार श्री वेन के इस बयान को खास महत्व दे रहे हैं कि ''भारत और चीन के 2200 साल पुराने रिश्तों में 99.99 प्रतिशत हिस्सा दोस्ती का है और केवल 0.01 प्रतिशत हिस्सा ही कड़वाहट का है जिसे अब भूल जाना चाहिए।''

चीनी चाशनी के समुद्र में इस सुई की नोक भर कड़वाहट से चीनी प्रधानमंत्री का मतलब 1962 में भारत पर चीन के उस सैनिक हमले से है जो चेयरमैन माओ ने भारत को 'सबक सिखाने' के लिए किया था और जिसमें भारत को बुरी तरह बेइज्जत करने के अलावा हथियाई गई हजारों वर्ग मील जमीन पर चीन आज भी कब्जा जमाए हुए है।

श्री वेन की इस भारत यात्रा की खुशी में लिए पिछले दिनों मुंबई में एक आठ दिवसीय महोत्सव मनाया गया जो संयोग से भारत–चीन कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने का भी अवसर था। इस त्यौहार के भारतीय संयोजक भारतीय जनता और सरकार को शायद यह समझाना चाह रहे थे कि हमें चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एनलाई के नारे 'हिंदी–चीनी भाई–भाई' को तो याद रखना चाहिए पर इस नारे की आड़ में भारत की पीठ में भोंके गए छुरे के जख्मों को भूल जाना चाहिए। लेकिन वे चीन सरकार को यह सलाह देने को तैयार नहीं हैं कि वह भी हमले में कब्जाई गई हजारों वर्गमील भारतीय जमीन वापस कर दे और भारत के खिलाफ अपनी चालों पर लगाम लगाए।

चीन से भारत की दोस्ती के ये समर्थक इस बात पर फूले नहीं समा रहे कि पिछले 20 साल में भारत–चीन व्यापार 3 अरब डालर से बढ़कर 60 अरब हो गया है। लेकिन सच यह है कि यह एकपक्षीय व्यापार है जिसमें चीन ने तो तैयार माल से भारतीय बाजार को पाटकर यहां के खिलौना, इलेक्ट्रोनिक सामान और हथकरधा, साड़ी तथा प्रिंटिंग जैसे सैंकडों उद्योगों के लाखों परिवारों के धंधे चौपट कर दिए हैं जबकि भारत से आयातित लोहे और दूसरे खनिजों के बूते पर चीन भारत की भीतरी और अंतर्राष्ट्रीय ताकत को कमजोर कर रहा है।

चीन के प्रति श्रद्धावान बिरादरी के कुछ भारतीय चीन–विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत यात्रा के दौरान श्री वेन घोषणा करेंगे कि जम्मू–कश्मीर के भारतीय नागरिकों को अब अलग कागज़ के बजाए उनके भारतीय पासपोर्ट पर वीज़ा दिया जाएगा। उनका दावा है कि इस चीनी कदम से भारत–चीन संबध फिर से मीठे हो जाएंगे। लेकिन बेचारे यह नहीं समझा पा रहे कि एक खुराफात को वापस ले लेने से चीन के वो पाप कैसे धुल जाएंगे जो वह भारत के खिलाफ पिछले साठ साल से लगातार करता आ रहा है?

असल में भारतीय राजनेताओं और विदेशनीति विशेषज्ञों के एक बड़े वर्ग की समस्या यह है कि वे नारेबाजी और दिखावेबाजी को ही कूटनीति का असली तत्व मानकर 'सफल' यात्राओं की उपलब्धियों पर कूदते फिरते हैं। चीन के मामले में तो अब यह एक लगभग असाध्य बीमारी का रूप ले चुकी है। हर बार ऐसी किसी चीनी पर उनका एकमात्र लक्ष्य यही रहता है कि किसी तरह की रिआयत देकर चीनी नेताओं के चेहरों पर मुस्कराहट लाई जाए और उनसे कोई मीठा बयान दिलाया जाए। नतीजा यह है कि हर ऐसी यात्रा के बाद भारत कुछ और खो बैठता है और चीन की मांगें पहले से और ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं। नतीजा वही कि नारों के बावजूद भारत–चीन संबंधें में लगातार तनाव बना रहता है।

अगर भारत को सचमुच चीन के साथ संबंध सुधारने हैं तो उसे अपनी दब्बू परंपरा को त्यागकर चीन के साथ बिना लाग लपेट के दो टूक बात करने का अंदाज़ अपनाना होगा। श्री वेन की भारत यात्रा के मौके पर भारत को चीन के उन सब कदमों पर सवाल उठाने चाहिएं जो वह तब से उठाता आ रहा है जबसे तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद भारत–चीन सीमा साझा हुई है।

पिछले साठ साल में चीन ने तिब्बत को अपनी सैनिक छावनी में बदलकर उस भारत–तिब्बत सीमा पर भारत के लिए भयंकर खतरे खड़े कर दिए हैं जो पिछले हजारों सालों से दुनिया की सबसे शांत सीमा थी। तिब्बत की जमीन का इस्तेमाल करके वह पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा के रास्ते भारत को घेरने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान में ग्वादर नौसैनिक अड्डा बनाकर और पाक कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते चीनी रेलवे लाइन को ग्वादर और ईरान तक बिछाने की योजना ने भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

नेपाल में भारत विरोधी वातावरण पैदा करने के अलावा 'सहायता' के नाम पर चीन ने वहां सड़कों का ऐसा नेटवर्क बना दिया है जिसे इस्तेमाल करके उसकी सेनाएं कभी भी भारत के दरवाजे पर आ सकती हैं। म्यांमार में हवाई पट्टियां और सड़कें बनाकर तथा कोको द्वीप में अंडमान के निकट नौसैनिक चौकी से उसने भारत की सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा पैदा कर दिया है। बांगला देश से सैनिक संधि करके और वहां भारत विरोधी आतंकवादियों को हर तरह की मदद देकर चीन ने सुरक्षा संतुलन भारत के खिलाफ कर दिया है। इसी तरह श्रीलंका में हंबनटोटा में नौसैनिक अड्डा विकसित करके तथा वहां एक और नए अड्डे पर काम शुरू करके चीन ने भारत की चारों ओर से सैनिक घेरेबंदी की पक्की व्यवस्था कर डाली है।

चीन की ओर से सबसे बड़ा खतरा भारतीय माओवादियों के रूप में विकसित हो रहा है। पशुपति से तिरुपति के बीच उनके फैलाव को देखकर लगता है कि इन्हें चीन सरकार उस दिन के लिए पाल पोस रही है जब चीनी नीतिकारों की घोषित योजना के तहत भारत के 'तीस टुकड़े' करने के अभियान को वह शुरू करेगी। चीन की यह नक्सली–दीवार भारत के लिए उस दिन बहुत घातक सिद्ध होगी जब नेपाल और बंगलादेश के रास्ते सिलिगुड़ी के निकट 'चिकन नेक' को दबाकर वह भारत के सात उत्तर–पूर्वी राज्यों को काटने के लिए सैनिक कार्रवाई करेगा।

ऐसे में सही नीति यही होगी कि भारत एकतरफा इश्क से मुक्ति पाए। श्री वेन की यात्रा पर राग दरबारी गाने और हिंदी–चीनी भाई–भाई का पुराना ढोल पीटने के बजाए भारत सरकार को जमीन पर चीनी असलियत समझते हुए बिना लाग लपेट के सीधी–सीधी बातचीत करनी चाहिए।

– विजय क्रान्ति

शिक्षा का माध्यम चीनी करने से तिब्बत के रेबकांग में उपजा आक्रोश

शेलकर चोएड मठ के दो भिक्षुओं तेंजिन गेफेल और नवांग को 12–12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि इसी मठ के एक अन्य भिक्षु को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस खबर में हालांकि सुनवाई और सजा सुनाए जाने की तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया।

(फायूल डॉट कॉम, 20 अक्टूबर, धर्मशाला) रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक चीन सरकार द्वारा तिब्बती क्षेत्र में एक स्कूल में शिक्षा की माध्यम भाषा को तिब्बती से बदलकर चीनी किए जाने पर तिब्बती छात्रों और बौद्ध भिक्षुओं ने विरोध में प्रदर्शन किया है। चीन सरकार ने अपने ताजा फैसले में तिब्बत के क्विंघई प्रांत के एक स्कूल की माध्यम भाषा तिब्बती से हटाकर चीनी कर दी है।

रेडियो फ्री एशिया ने इस क्षेत्र में अपने एक संपर्क सूत्र के हवाले से बताया कि क्विंघई के माल्हो जिले में रेबकांग में मंगलवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों तिब्बती छात्रों ने हिस्सा लिया। इस क्षेत्र के छह स्कूलों – दि फर्स्ट नेशनलिटीज मिडल स्कूल ऑफ रेबकोंग (तोंगरेन) दि तोंगरेन काउंटी यिफू नेशनलिटीज मिडल स्कूल, दि तोंगरेन जिला आवासीय विद्यालय,दि तोंगरेन मॉडर्न मेडीसिन कॉलेज, दि माल्हो नेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दि माल्हो नेशनलिटीज मिडल स्कूल– के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रेडियो ने अपने सूत्र के हवाले से बताया कि प्रदर्शनकारी तिब्बती और चीनी भाषा में बैनर हाथों में लिए हुए थे, जिस पर लिखा था ''इक्वलिटी एमंग नेशनलिटीज यानी, सभी राष्ट्रीयताओं में समानता'' और ''एक्सपेंड दि यूज ऑफ टिबेतन लैंग्वेज यानी, तिब्बती भाषा का उपयोग बढ़ाएं''। एक बौद्ध भिक्षु ने रेडियो को बताया कि छात्रों ने भिक्षुओं को इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने से मना किया था। इसके बावजूद क्षेत्र के रेबकांग रोंगपो मठ के भिक्षुओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

एक भिक्षु ने रेडियो पर कहा कि छात्रों को डर था कि भिक्षुओं के प्रदर्शन में हिस्सा लेने से चीन सरकार अधिक संवेदनशील हो जाएगी और प्रदर्शन का दमन करने के लिए हथियारबंद दस्ते को भेज देगी। तोंगरेन के एक तिब्बती निवासी ने कहा कि प्रदर्शन तोंगरेन नेशनलिटीज मिडल स्कूल में सुबह शुरू हुआ और दोपहर दो बजे तक जारी रहा। रेडियो ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि 20 से 30 पुलिस वाहनों ने प्रदर्शनकारियों को घेर लिया, हालांकि उन्होंने किसी को हिरासत में नहीं लिया। रेबकांग के ही एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि जिला अधिकारी अह गेंडुन, माल्हो जिले के उप प्रमुख और माल्हो शिक्षा विभाग के प्रमुख सेरु गियाल्तसेन ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि वे जिले और प्रांत के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय सचिव और अध्यक्ष ने हाल में हुई बैठक में आदेश दिया था कि किताबों की भाषा को चीनी में रखा जाए। उन्होंने इस फैसले पर कोई बहस नहीं होने दिया। उसने कहा कि प्रांतीय अधिकारियों ने तिब्बती शिक्षकों को माध्यम भाषा परिवर्तन की कार्यशाला में भाग लेने का आदेश दिया है। उसने कहा कि इस फैसले के कारण कई तिब्बती शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी जगह चीनी लोगों को नौकरी मिलेगी। तिब्बती समुदाय के लिए यह सर्वाधिक चिंता का विषय है। हाल में इन स्कूलों में तिब्बतियों की संख्या भी घटाई गई है और कई तिब्बती शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए बर्खास्त कर दिया गया है।

तिब्बत के धिंगरी में 3 भिक्षुओं को कारावास की सजा

(फायूल डॉट कॉम, 26 अक्टूबर, धर्मशाला) तिब्बत के दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र के शिगात्से जिले के धिंगरी में 3 बौद्ध भिक्षुओं को अलग–अलग अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। यह खबर ''वॉयस ऑफ तिब्बत'' में सोमवार को प्रसारित की गई।

शेलकर चोएड मठ के दो भिक्षुओं तेंजिन गेफेल और नवांग को 12–12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि इसी मठ के एक अन्य भिक्षु को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस खबर में हालांकि सुनवाई और सजा सुनाए जाने की तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इन तीनों भिक्षुओं को और 10 अन्य भिक्षुओं को तब गिरफ्तार किया गया था, जब चीनी अधिकारियों का एक दल इस मठ में बौद्ध भिक्षुओं पर देशभक्ति का एक नया पाठ थोपने के लिए आया था। भिक्षुओं को उनके धार्मिक नेता परमपावन दलाई लामा की आलोचना करने को कहा गया। लेकिन बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की चेतावनी के बावजूद भिक्षुओं ने इसका विरोध किया और कहा कि दलाई लामा उनके मूल गुरु हैं और वे उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं।

19 मई 2008 को कुल 13 भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 10 को साल 2009 में छोड़ दिया गया था। इस घटना के बाद स्थानीय चीनी अधिकारियों ने मठों में नए भिक्षुओं की नियुक्ति बंद कर दी है।

तिब्बत में भाषा पर विरोध जारी, 20 तिब्बती छात्र हिरासत में

(फायुल डॉट कॉम, 25 अक्टूबर, धर्मशाला) चीन सरकार की शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। रविवार को चेंत्सा काउंटी में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया और मांग की चीन सरकार तिब्बत के स्कूलों में तिब्बती भाषा को हटाकर उसकी जगह चीनी भाषा थोपने के फैसले को वापस ले। जानकारों को कहना है कि शनिवार को छाबछा काउंटी में विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया।

जानकार सूत्रों ने बताया कि रविवार को सुबह 7.30 बजे शुरू हुए प्रदर्शन में शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। चेंत्सा के छात्रों ने 19 और 21 अक्टूबर को भी प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह प्रदर्शन होने की खबर मिली है। सबसे पहले रेबकांग में

छह स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और ''लोगों की समानता और भाषाई आजादी'' की मांग की।

पिछले कुछ दिनों में छबछा, चेंत्सा, खिघा और गोलोक में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीजिंग में करीब 400 छात्रों ने प्रदर्शन कर जबरदस्ती चीनी भाषा थोपने का विरोध किया। इस बीच शिक्षकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर 15 अक्टूबर को क्विंघई प्रांत की सरकार से आग्रह किया कि वह स्कूलों में तिब्बती भाषा को हटाकर उसकी जगह चीनी भाषा को थोपने के फैसले को वापस ले। तिब्बती भाषा के खबडा डॉट ऑर्ग ब्लॉग पर कहा गया है कि उसके पास इस पत्र का एक हिस्सा है। इस अधूरे पत्र में जैसा कि ब्लॉग पर कहा गया है, 103 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जबकि वास्तविक पत्र में करीब 300 लोगों के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र में चीनी संविधान का हवाला देकर कहा गया है कि इसकी धारा 4 में सभी जातीय समूहों को उनकी बोली और भाषा का विकास करने की आजादी है। साथ ही अपनी परंपरा और तौर–तरीकों की रक्षा करने और उसका विकास करने की आजादी है।

दलाई लामा लियु जियाबाओ को छोड़ने की अपील करने वाले नोबेल विजेताओं में शामिल

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 26 अक्टूबर) परमपावन दलाई लामा सहित 15 नोबल शांति पुरस्कार विजेताओं ने एक खत पर हस्ताक्षर कर जी–20 से निवेदन किया है कि वह चीन से मांग करे कि वह मानवाधिकार समर्थक और नोबल पुरस्कार विजेता लियु जीयाबाओ को मुक्त कर दें। केप टाउन के अवकाशप्राप्त आर्कबिशप डेसमंड टुटु की पहल पर लिखे गए और 15 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में लिखा गया है कि चीन द्वारा डॉ. लियु को छोड़ना वहां हाल के वर्षों में हुए अभूतपूर्व बदलाव को ही रेखांकित करेगा। यह खत जी–20 के नेताओं को 25 अक्टूबर को भेजा गया था।

पत्र में लिखा गया है, 'हम पुरजोर तरीके से यह आग्रह करते हैं कि आपकी सरकारें चीन की सरकार से आग्रह करें कि वह लियु जियाबाओ की पत्नी ''लियु जिया'' को हाउस एरेस्ट से मुक्त करे और वह जिससे भी चाहे उन्हें आजादी के साथ बात करने दे। जी–20 सम्मेलन के एक अंग के तौर पर आपमें से हर कोई 10–11 नवंबर को दक्षिण कोरिया के सियोल में चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ से मिलेंगे। इस सम्मेलन में आपको डॉ. लियु के कारावास के बारे में बात करने समय और अवसर दोनों मिलेगा। हम आपसे पुरजोर आग्रह करते हैं कि आप निजी तौर पर चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ पर दबाव डालें कि डॉ. लियु को छोड़ना न सिर्फ स्वागत योग्य कदम है, बल्कि जरूरी है। अन्य हस्ताक्षर करने वालों में थे कार्लो फिलिप जिमेंस बेलो, जिमि कार्टर, एफ.डब्ल्यू. डी क्लार्क, शिरिन एबादी, जॉन ह्यूम, मैरिड मैग्वायर, वांगरी मथाई, डैविड ट्रिंबल, रिगोबेर्टा मेंचु टुम, लेक वालेसा, एली विजेल, बेटी विलियम्स और जोडी विलियम्स।

युगुर वासियों का भाषाई प्रदर्शन को समर्थन

(आरएफए डॉट ऑर्ग, 27 अक्टूबर)

युगुर वासियों ने पश्चिमी चीन में तिब्बतियों के प्रदर्शन का समर्थन किया है और चीन की भाषा नीति पर आपत्ति जताई है। युगुर निवासियों और बुद्धिजीवियों के मुताबिक युगुर वासियों के द्वारा तिब्बतियों के अपने अधिकारियों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का साथ देने के बाद अब चीन इंटरनेट पर दमनात्मक कार्रवाई करने की ओर अग्रसर हो रहा है। तिब्बत के छात्र पिछले दो सप्ताह से चीन के पश्चिमी प्रांत क्विंघई में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि चीन इस क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों में चीनी भाषा माध्यम में पाठ्य पुस्तक थोप सकता है। शिनजियांग के एक छात्र ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बीजिंग तक फैलने के बाद चीन इन खबरों को युगुर वासियों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि युगुर वासी भी अपनी भाषा को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है।

एक अन्य छात्र ने कहा कि स्थानीय सरकार कॉलेजों के वेबसाइटों और सूचनाओं पर नियंत्रण लगा रही है, लेकिन हमें चीन में रहने वाले अपने दोस्तों से पहले ही तिब्बत के प्रदर्शनों और बीजिंग के अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय से सूचना मिल चुकी है।

उसने कहा कि ''उन्होंने बताया है कि युगुर विश्वविद्यालय के बीजिंग में रहने वाले छात्रों से तिब्बत में हो रहे प्रदर्शन की जानकारी मिली और वे इस खबर से बहुत उत्साहित हैं। यहां तक कि कजाक छात्र भी तिब्बतियों के समर्थन में हैं।''

एक छात्र ने अपना नाम और स्थान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि ''लेकिन चीन और यहां का हर विश्वविद्यालय अपने छात्रों पर कड़ा नियंत्रण लगा रहा है। यहां तक कि केंद्रीय चीनी क्षेत्रों में रहने वाले शिनजियांग के छात्रों पर भी नियंत्रण लगाया जा रहा है।''

लोकप्रिय वेबसाइट और युगुर वासियों से संबंधित मामलों पर एक ऑनलाइन बहस फोरम युगुरबिज डॉट नेट (Uyghurbiz.net) ने लिखा है कि चीन के केंद्रीय क्षेत्रों में युगुर के छात्रों के लिए लगाए जाने वाले ''शिनजियांग कक्षाओं'' के हर छात्र को सुरक्षा अधिकारियों ने एक–एक कर बुलाकर तिब्बत में चल रहे भाषाई प्रदर्शन को समर्थन देने वाली गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा है। खबरों में बताया गया है कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों को इन गतिविधियों से दूर रखने की हिदायत दी गई है। युगुर छात्रों को खाना खिलाने वाले रेस्टोरेंटों, जहां मुस्लिम तरीकों से खाना बनाया जाता है, वहां किसी तरह की अस्थिरता की संभावना को समाप्त करने के लिए विशेष पकवान परोसे जा रहे हैं। एक युगुर शिक्षक ने भी अपना नाम छुपाए रखने की शर्त पर बताया कि इस क्षेत्र में तिब्बत

केप टाउन के अवकाशप्राप्त आर्कबिशप डेसमंड टुटु की पहल पर लिखे गए और 15 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में लिखा गया है कि चीन द्वारा डॉ. लियु को छोड़ना वहां हाल के वर्षों में हुए अभूतपूर्व बदलाव को ही रेखांकित करेगा। यह खत जी–20 के नेताओं को 25 अक्टूबर को भेजा गया था।

के प्रदर्शन को पूरा समर्थन मिल रहा है। उसने कहा कि हमें भी समान समस्या झेलनी पड़ रही है, इसलिए यहां हर शिक्षक और छात्र तिब्बतियों के प्रदर्शन को समर्थन दे रहा है। उसने कहा कि हमारे छात्रों को हमारी भाषा सीखनी चाहिए ताकि हम युगुर बने रहें। शिक्षक ने कहा कि उइगर समुदाय हाल ही में शिनजियांग में नियुक्त नए गवर्नर नूर बेकरी और अन्य अधिकारियों से बहुत आजिज हैं, जो कहते हैं कि वे बीजिंग के हित में काम कर रहे हैं। उसने कहा कि चीन की सरकार यहां द्विभाषी व्यवस्था करना चाहती है। लेकिन स्थानीय सरकार हमसें यह नहीं पूछती कि हम क्या चाहते हैं। हम इस नीति से सहमत नहीं हैं। उसने कहा कि यह सरकार सभी गलत काम कर रही है। सरकार को द्विभाषी व्यवस्था नहीं थोपनी चाहिए, खास तौर से किंडरगार्डेन में पढ़ने वाले बच्चों पर। उसने कहा कि मंदारिन चीनी भाषा को जबरदस्ती थोपने का जिंजियांग की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

द्विभाषा पद्धति लागू होने के बाद कई ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा जिन्हें चीनी भाषा नहीं आती थी। यह बहुत बुरा हुआ। कई छात्रों ने भी पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि वे इसके कारण पढ़ने में रुचि नहीं ले पाते हैं। बीजिंग के अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और एक वेबसाइट Uighurbiz.net के संचालक इलहाम तोहती ने कहा कि उनके विश्वविद्यालय के छात्र तिब्बती प्रदर्शन में हिस्सा लेने को इच्छुक हैं।

उन्होंने कहा, "क्विंघई में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से ही हमारे विश्वविद्यालय के छात्र इस प्रदर्शन के साथ हैं। कुछ छात्र हमारे कार्यालय में आकर बोले कि वे तिब्बतियों के प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम बिना हिस्सा लिए भी समर्थन कर सकते हैं।" प्रोफेसर ने कहा कि अगर हम प्रदर्शन करते हैं, तो समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जबसे तिब्बत में प्रदर्शन शुरू हुआ है हमारे ऊपर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। एक दिन एक अधिकारी ने आकर हमसे पूछा कि हमारी तिब्बतियों के प्रदर्शन पर क्या राय है। हमने कहा कि हमें शिनजियांग में सतर्क रहना चाहिए। चीन की सरकार तिब्बत से बहुत पहले शिनजियांग में द्विभाषी व्यवस्था शुरू कर चुकी है, जिसका हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने पिछले साल रुमकी में हुए प्रदर्शन, जिसमें चीन सरकार के मुताबिक करीब 200 लोगों की जान गई थी, का हवाला देकर कहा कि यदि चीन सरकार अपनी नीति नहीं बदलती है, तो युगुर के लोग फिर वैसा ही प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रोफेसर ने इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए कहा कि चीनी सरकार को अपनी नीति पर दोबारा सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि चीन सरकार कोई नया तरीका सोचेगी, जिसमें युगुर के लोगों को अधिक आजादी मिले। यदि चीन शिनजियांग को अपने साथ बनाए रखना चाहता है, तो उसे यह करना ही होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय एशिया और शिनजियांग में करोड़ों उइगर रहते हैं। उइगर समुदाय के लोगों का कहना है कि चीन के उत्तर–पश्चिमी प्रांत के विकास की योजना के बावजूद उइगरों के साथ भेदभाव होता है और हम पर धार्मिक विश्वास थोपे जा रहे हैं। हमारी नौकरी छिनी जा रही है। चीनी अधिकारियों ने उधर उइगर के एक समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उसका अलकायदा से रिश्ता है।

कई तिब्बती लेखकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बर्बर एवं निष्ठुर दमन के खिलाफ लिखा है और सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस मामले को बातचीत से हल किया जाए। कुंथार ने बताया, "लेकिन चीनी अधिकारी ऐसे लेखकों को अलगाववादी एवं विद्रोही ठहरा देते हैं और उनके ऊपर कई तरह के गलत आरोप लगाकर जेल में ठूंसकर उनका मुंह बंद कर दिया गया है।

टोक्यो इंटरनेशनल पेन कांग्रेस में शामिल हुए तिब्बती लेखक

(टिबेट हाउस जापान, टोक्यो, 1 अक्टूबर)

धर्मशाला, भारत में रहने वाले तिब्बती लेखक एवं अनुवादक श्री कुंथार टोक्यो में आयोजित 76वें इंटरनेशनल पेन कांग्रेस 2010 में शामिल हुए। इंटरनेशनल पेन के जापान चैप्टर और वासेडा यूनिवर्सिटी ने 23 सितंबर से एक सप्ताह तक इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय था, 'पर्यावरण एवं साहित्य–शब्दों से क्या हो सकता है।'

इस सम्मेलन में 128 देशों के 600 लेखक शामिल हुए। वासेडा विश्वविद्यालय में सम्मेलन का उद्घाटन साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता चीनी लेखक गाओ शिंगछियान ने किया। शिंगछियान इस सम्मेलन के मुख्य वक्ताओं में से थे। सम्मेलन में शामिल लोगों को कई समितियों में बांट कर अलग–अलग विचार और लेखन की स्वतंत्रता पर चर्चा की गई। 'जेल में लेखक' और 'अनुवाद एवं भाषाई अधिकार' विषय पर बनी समिति में कुंथार ने हिस्सा लिया। कुंथार ने यह मसला उठाया कि तिब्बत में मार्च 2008 की घटना के बाद 40 से ज्यादा तिब्बती लेखकों और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार एवं प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि कई तिब्बती लेखकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बर्बर एवं निष्ठुर दमन के खिलाफ लिखा है और सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस मामले को बातचीत से हल किया जाए। कुंथार ने बताया, "लेकिन चीनी अधिकारी ऐसे लेखकों को अलगाववादी एवं विद्रोही ठहरा देते हैं और उनके ऊपर कई तरह के गलत आरोप लगाकर जेल में ठूंसकर उनका मुंह बंद कर दिया गया है। तिब्बती लेखकों ने सिर्फ चीनी संविधान में वर्णित 'विचार एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया था। चीन का प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर सकती, उसे देश के संविधान का पालन करना चाहिए। तिब्बती लेखकों को बंदी बनाकर और उन्हें प्रताड़ित करके सरकार देश के कानून का उल्लंघन कर रही है।" उन्होंने तिब्बती भाषा की गंभीर हालत के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। "चीन तिब्बती क्षेत्र को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उसने तिब्बती को इस क्षेत्र की दूसरी भाषा बना दिया है। ज्यादातर चौराहों और सड़कों का नाम चीनी भाषा में रखा गया है। तिब्बत की ज्यादातर पर्वतों और नदियों का नाम भी बदलकर चीनी भाषा में कर दिया गया है। अनुवाद एवं भाषाई अधिकार पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'तिब्बती भाषा को नष्ट

करने और चीनी भाषा थोपने की यह नीति तिब्बती भाषा के लिए बड़ा खतरा बन गई है।" इस सम्मेलन में चीनी मूल के कई लेखक शामिल हुए जिनमें कई प्रख्यात लेखक शामिल थे। श्री कुंथार के कथन पर चीनी प्रतिनिधि भी सहमत थे, लेकिन उन्होंने काफी मजबूती से यह बात रखी कि सिर्फ तिब्बत के लोगों को ही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा रहा बल्कि पूरे चीन में इस तरह की आज़ादी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सभी तरफ से एक संयुक्त केंद्रित प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कम्युनिस्ट सरकार लोगों की इच्छा का पालन करे। कई चीनी लेखकों ने बताया कि ज्यादातर चीनी नागरिकों को परमपावन दलाई लामा की शिक्षाओं और स्वायत्तता के उनके विचार के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसकी पहली वजह तो है दलाई लामा से जुड़ी किसी भी चीज को प्रतिबंधित रखने की कठोर नीति और दूसरी वजह है दलाई लामा के शिक्षण का चीनी भाषा में अनुवाद न होना। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे परम पावन दलाई लामा के शिक्षण को चीनी जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए।

पेन सम्मेलन के प्रस्तावों को संकलित करते हुए आयोजकों ने टोक्यो दूतावास को कई ज्ञापन दिए जिसमें मांग की गई थी कि चीन में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल की जाए और चीन, तिब्बत एवं अन्य स्वायत्तशासी क्षेत्रों में जेल में बंद किए गए सभी लेखकों को तत्काल रिहा किया जाए। श्री कुंथार ने कहा कि यह सम्मेलन काफी शिक्षणप्रद रहा और इसमें शामिल सदस्यों से तिब्बत में शांति एवं आज़ादी के लिए तिब्बतियों के संघर्ष को मजबूत समर्थन भी मिला। वह किसी भी ऐसे चीनी बुद्धिजीवी से मिलने के लिए तैयार थे जो स्पष्टवादी हो और परमपावन दलाई लामा की मध्यम मार्ग नीति और अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर उनसे विचारों का आदान–प्रदान करने को तैयार हो। कुंथार धर्मशाला में रहने वाले एक तिब्बती लेखक एवं अनुवादक हैं। वह पेन की धर्मशाला शाखा के उपाध्यक्ष हैं। उनके प्रसिद्ध अनुवाद कार्य में 'गंसेन्ग की नांर्ड्र' शामिल है जो मार्च 2008 की घटना पर तिब्बती लेखिका सुश्री वूएजर की डायरी है। उन्होंने परमपावन दलाई लामा की तीन श्रृंखला वाली पुस्तक 'शिडे, द पीस' का चीनी भाषा में अनुवाद किया है।

'सॉलिडेरिटी' की 30वीं वर्शगांठ पर परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि पोलैंड के दौरे पर

(टिबेट डॉट नेट, लंदन, 5 अक्टूबर)

पोलैंड में पहले स्वशासन ट्रेड यूनियन 'सॉलिडेरिटी' की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर लेक वालेसा फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में परमपावन दलाई लामा के लंदन में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि श्री थुबतेन सामदुप को भी जाने का न्योता मिला था और वह इसमें शामिल हुए। 'सॉलिडेरिटी' (एकात्मता) के जन्म स्थान उत्तरी पोलैंड के शहर डांस्क में 29 सितंबर को शुरू यह समारोह तीन दिन तक चला। दिसंबर, 2008 में परमपावन ने भी डांस्क का दौरा किया था। वह वहां पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति लेक वालेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 25वीं वर्षगांठ पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए लेक वालेसा फाउंडेशन के निमंत्रण पर गए थे। परमपावन ने वहां विश्व युवा मंच के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित किया था जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। इस साल आयोजित कार्यक्रम में 29 सितंबर को एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया गया और इसके बाद 30 सितंबर को 'यूरोप एवं विश्वः पोलैंड के सॉलिडेरिटी आंदोलन की जीत के 30 साल बाद' विषय पर आयोजित दिन भर का सम्मेलन हुआ। इसमें सम्मेलन में शामिल होने और संबोधित करने वाली प्रमुख हस्तियों में पौलैंड के पूर्व राष्ट्रपति लेक वालेसा, डांस्क के मेयर पावेल एडैमोविस्कज और पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री ब्रोनिस्ला कोमोरोवस्की और दुनिया के कई हिस्सों से आए अन्य गणमान्य अतिथि शामिल थे। लेक वालेसा फाउंडेशन का तीसरा वार्षिक लेक वालेसा अवार्ड चैरिटी पोलिश ह्यूमनिटेरियन एक्शन की प्रमुख सुश्री जैनिना ओछोज्सका को दिया गया। परमपावन के प्रतिनिधि थुबतेन सामदुप ला ने इसके लिए ओछोज्सका को बधाई दी।

सामदुप ने तीसरे युवा मंच के 29 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और यूरोपीय सॉलिडेरिटी सेंटर द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय परियोजना 'डांस्क स्टेशन' के भागीदारों से मिला।

युवाओं के इस कार्यक्रम में थुबतेन ने अहिंसक संघर्ष के बुनियादी अर्थ पर प्रकाश डाला जो सॉलिडेरिटी आंदोलन और पोलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था और जो इस हिंसक समय में तिब्बतियों के अपनी पहचान एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे संघर्ष को एक अलग पहचान देता है। उन्होंने तिब्बती नेतृत्व के भविष्य और तिब्बती एवं चीनी लोगों के बीच सीधा संवाद बनाने की गतिविधियों के बारे में कार्यक्रम में शामिल लोगों द्वारा किए गए कई सवालों के जवाब भी दिए। इसके बाद 1 अक्टूबर को सिविक एकेडमी से जुड़े लोगों के साथ आयोजित रात्रिभोज में श्री सामदुप को फिर से तिब्बत के मसले पर बोलने और पूरे पूर्वी यूरोप से आए हुए युवा नेतृत्व के सवालों के जवाब देने का मौका मिला।

सामदुप ने डांस्क के अपने तीन दिवसीय दौरे के बारे में कहा, 'पोलैंड के सॉलिडेरिटी आंदोलन की 30वीं वर्षगांठ के उत्सव में परमपावन दलाई लामा का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात थी। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति लेक वालेसा और सॉलिडेरिटी आंदोलन के अन्य महारथियों से मिलना मेरे लिए एक विनम्र अनुभव था। जब मैने युवा मंच को संबोधित किया तो मैंने उनसे आग्रह किया कि उनके ऊपर अपने पूर्वजों की विरासत को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने और सॉलिडेरिटी आंदोलन की

कुंथार धर्मशाला में रहने वाले एक तिब्बती लेखक एवं अनुवादक हैं। वह पेन की धर्मशाला शाखा के उपाध्यक्ष हैं।उनके प्रसिद्ध अनुवाद कार्य में 'गंसेन्ग की नांर्ड्र' शामिल है जो मार्च 2008 की घटना पर तिब्बती लेखिका सुश्री वूएजर की डायरी है। उन्होंने परमपावन दलाई लामा की तीन श्रृंखला वाली पुस्तक 'शिडे, द पीस' का चीनी भाषा में अनुवाद किया है।

अतुलनीय भावना को शेष दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। यह पोलैंड की तरफ से दुनिया को दिया जाने वाला सबसे महान उपहार है।"

तिब्बतियों के मतदान में व्यवधान डालने की दुनिया भर में निंदा

"तिब्बत के मसले पर मैकमिलन स्कॉट चीन को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बातचीत शुरू करे और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि बैरोनेस एस्थॉन को दलाई लामा से मिलना चाहिए ताकि तिब्बत के लिए यूरोपीय संघ के एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति हो सके।"

(आरएफए, 7 अक्टूबर)

निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की निर्वासित सरकार के लिए तिब्बती शरणार्थियों के बीच चल रही मतदान प्रक्रिया में नेपाली पुलिस के व्यवधान डालने पर चिंता जताते हुए दलाई लामा के विशेष दूत ने कहा कि ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार चीन के दबाव में काम कर रही है। वाशिंगटन में दलाई लामा के प्रतिनिधि लोदी ग्यारी नेपाल में अमेरिकी राजदूत स्कॉट डेलिसी से वाशिंगटन स्थित विदेश मंत्रालय के ऑफिस में 5 अक्टूबर को मिले और उन्होंने नेपाल सरकार की कार्रवाई को "चिंताजनक और खेदजनक" बताया। निर्वासित तिब्बती सरकार ने एक बयान में बताया, "उनकी चिंता सिर्फ तिब्बतियों को लेकर नहीं , बल्कि नेपाल के एक संप्रभु देश के रूप में पड़ने वाले निहितार्थ को लेकर भी है। नेपाल अब चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र की तरह हो गया है। वह इस बात से काफी चिंतित हैं क्योंकि नेपाल और तिब्बत के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं।" बयान में कहा गया है, "इस बात को लेकर हर तरफ चिंता है और अमेरिकी राजदूत ने इस मामले को देखने का वायदा किया है। गौरतलब है कि नेपाल पुलिस ने सख्त तेवर दिखाते हुए रविवार को हिमालयी देश में हजारों तिब्बतियों द्वारा एक नई निर्वासित सरकार चुनने के लिए शुरू प्रक्रिया को रोक दिया। पुलिस ने राजधानी काठमांडू में बनाए गए तीन मतदान केंद्रों पर धावा बोलकर मतदान पेटियों को जब्त कर लिया। राजधानी में रहने वाले करीब 9000 निर्वासित तिब्बतियों के बीच यह चुनाव प्रकिया शुरू की गई थी। चीन के प्रति नेपाल के बढ़ते राजनीतिक झुकाव से निर्वासित तिब्बतियों का जीवन कठिन होता जा रहा है जो पड़ोसी तिब्बती क्षेत्र में चीनी कब्जे का विरोध कर रहे हैं। नेपाल में चीनी राजनय केंद्रों के बाहर प्रदर्शन करने वाले तिब्बतियों को अक्सर पीटा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, धमकाया जाता है या उन्हें जबरन भारत भेज दिया जाता है। गौरतलब है कि नेपाल के साथ तिब्बत की काफी लंबी सीमा जुड़ी है। तिब्बती में चीनी कब्जे के विरोध में जन क्रांति असफल हो जाने के बाद साल 1959 में जब दलाई लामा को निर्वासित होकर भारतीय शहर धर्मशाला में अपना पड़ाव बनाना पड़ा तब उनके साथ हजारों अन्य तिब्बतियों ने भी देश छोड़ दिया जिनमें से करीब 20,000 तिब्बती नेपाल में रहते हैं। अगले साल निर्वासित तिब्बत की नई संसद के गठन और प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए करीब 80,000 निर्वासित तिब्बतियों के बीच चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है।

काठमांडू के पुलिस प्रमुख रमेश खरेल ने इस बात की पुष्टि की है कि मतदान पेटियां जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई 'अवैध मतदान' को रोकने के लिए की गई। उन्होंने एएफपी को बताया, "तिब्बती नेपाल में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। उनके द्वारा यहां चुनाव करना अवैध है। इसलिए हमने मतदान पेटियां जब्त कर लीं। इस घटना के बाद तिब्बत पर सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनपीएटी) ने नेपाल सरकार से मांग की है कि, "वह मतदान पेटियों को तत्काल नेपाल में तिब्बती चुनाव आयोग के वैधानिक प्रतिनिधियों को सौंपे।" इस संगठन से दुनिया भर की 30 से ज्यादा संसद के 133 सांसद जुड़े हुए हैं। आईएनपीएटी के सह अध्यक्ष मटेओ मेकाक्की ने कहा कि इस संगठन के सांसदों को "इस अवांछित कार्रवाई से गहरा सदमा पहुंचा है।"

मेकाक्की ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस की यह कार्रवाई काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की मांग पर की गई है। आईएनपीएटी ने कहा कि उसे आशंका है कि मतदान पेटियां जब्त करने की पुलिसिया कार्रवाई के वीडियो फुटेज प्रसारित होने से वैश्विक मंच पर नेपाल की छवि खराब होगी और यह नेपाल एवं तिब्बत के बीच सदियों चले आ रहे मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों के पूरी तरह खिलाफ है।

यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता ने तिब्बत पर वार्ता फिर शुरू करने का समर्थन किया

(टिबेट डॉट नेट, 7 अक्टूबर, ब्रसेल्स)

ब्रसेल्स में 6 अक्टूबर को 13वें ईयू–चीन सम्मेलन में यूरोपीय संघ और चीन के नेताओं की मुलाकात को देखते हुए यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष ने आह्वान किया है कि तिब्बत के मसले को हल करने के लिए चीनी नेतृत्व और परमपावन दलाई लामा के दूतों के बीच वार्ता तत्काल शुरू की जाए। यूरोपीय संसद में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र के उपाध्यक्ष श्री एडवर्ड मैकमिलन स्कॉट ने 6 अक्टूबर को जारी बयान में कहा है, "तिब्बत के मसले पर मैकमिलन स्कॉट चीन को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वह दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बातचीत शुरू करे और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि बैरोनेस एस्थॉन को दलाई लामा से मिलना चाहिए ताकि तिब्बत के लिए यूरोपीय संघ के एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति हो सके।" यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष ने यह भी उम्मीद जताई कि ब्रिटेन की गठबंधन सरकार तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता को पूरी तरह मान्यता देने के लेबर सरकार के निर्णय को रद्द कर देगी।

चीन–तिब्बत मैत्री संघों ने लिउ जियाबाओ के समर्थन के लिए परमपावन की तारीफ की

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 13 अक्टूबर)

आस्ट्रेलिया स्थित चीन–तिब्बत मैत्री संघों ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लिउ जियाबाओ का समर्थन

करने के लिए परमपावन दलाई लामा और तिब्बती जनता के लिए आभार प्रकट किया है। मेलबोर्न में चीन–तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष श्री यु शी शिन ने आस्ट्रेलिया में तिब्बत कार्यालय को भेजे पत्र में कहा है, "चीन–तिब्बत मैत्री संघ और लोकतांत्रिक चीन के लिए महासंघ (आस्ट्रेलिया) की तरफ से मैं परमपावन दलाई लामा और तिब्बती जनता के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले श्री लिउ जियाबाओ का समर्थन किया। हम तिब्बतियों से आह्वान करना चाहते हैं कि वे हमारी इस खुशी में शरीक हों। यह पुरस्कार सचाई के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन को प्रदर्शित करता है और इससे हमारा भरोसा और बढ़ा है कि हमारी आकांक्षाएं निश्चित रूप से एक दिन पूरी होंगी। सिडनी में चीन–तिब्बत मैत्री संघ के कार्यकारी प्रमुख शी गो यिन द्वारा तिब्बत कार्यालय को भेजे एक अन्य पत्र में कहा गया है, "जैसे ही श्री लिउ जियाबाओ को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई, तत्काल परमपावन दलाई लामा ने उनको अपनी हार्दिक बधाई दी। मैंने इस समाचार को चीन में इंटरनेट के माध्यम से बने अपने दोस्तों तक पहुंचाया।" यहां 9 अक्टूबर को करीब 50 चीनी लोग जिनमें लोकतांत्रिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ थे, लिउ जियाबाओ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की खुशी मनाने के लिए जुटे। इस समारोह के सह आयोजक लोकतांत्रिक चीन के लिए महासंघ के अध्यक्ष श्री क्विन जिन ने कहा, "हमारा मानना है कि परमपावन दलाई लामा से मिले समर्थन ने लिउ जियाबाओ को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समर्थन के लिए हम परमपावन को धन्यवाद देते हैं।"

'मंगोलिया और तिब्बत के बीच 1913 का समझौता' विषय पर मंगोलिया में संगोष्ठी का आयोजन

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 20 अक्टूबर)

'मंगोलिया और तिब्बत के बीच 1913 का समझौता' विषय पर मंगोलिया के उलनबटार शहर में 13 से 14 अक्टूबर तक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन मंगोलिया की राष्ट्रीय इंटेलीजेंस एकेडमी के जर्नल 'द इंडीपेंडेंस' के संपादकीय बोर्ड द्वारा किया गया था। इसमें मंगोलिया, भारत, अमेरिका, कोरिया, रूस, कनाडा, ताइवान, जापान, हॉलैंड और जर्मनी के 27 विद्वान शामिल हुए। इस दौरान निबंध पाठ और गर्मागर्म बहसों का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी का उद्देश्य था, मंगोलियाई और विदेशी विद्वानों के अनुसंधान परिणामों को पेश करना और 1913 में मंगोलिया एवं तिब्बत के बीच हुए मैत्री एवं गठबंधन समझौते पर दस्तखत की तर्कसंगतता पर विचारों को साझा करना और उस समय के सभी राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मसलों एवं दूसरे देशों के रवैए पर विचारों का आदान–प्रदान करना। 'द इंडीपेंडेंस' के प्रधान संपादक प्रोफेसर ए. टुवशिंटग्स और निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य श्री कालसांग ग्यालत्सेन ने 13 अक्टूबर को संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में छह सत्र आयोजित किए गए। इनमें प्रोफेसर सर्गियस एल कुजमिन का 'एक वैध अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में 1913 में हुए तिब्बत एवं मंगोलिया का समझौता' विषय पर वार्ता जिसकी अध्यक्षता श्री ताशी सेरिंग ने की, तिब्बती इतिहासकार एवं विद्वान डॉ. माइकल वान वाल्ट वान प्राग की 'अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 1913 के मंगोलिया–तिब्बत समझौते की प्रकृति पर नजर' विषय पर वार्ता और प्रोफेसर उदो बर्मान की 'राज्य की प्रभुसत्ता और मंगोलिया–तिब्बत समझौता (1913) पर वार्ता शामिल थी। भारत स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के एक प्रतिनिधि छुंग सेरिंग ने 'तिब्बत एवं मंगोलिया के बीच 1913 में हुए समझौते की पृष्ठभूमि और महत्व' पर प्रकाश डाला। 14 अक्टूबर को इस संगोष्ठी के समापन सत्र के बाद राजदूत रावदान बोल्ड ने इसमें शामिल लोगों के स्वागत में मार्शल महल में एक खास रात्रिभोज का आयोजन किया और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। तिब्बती, मंगोलियाई, रूसी, अंग्रेजी और चीनी भाषा में किए गए गहन अनुसंधान के आधार पर सदस्यों ने इस बहस का समापन एकमत से इस बात पर सहमत होते किया कि '1913 के मंगोलिया–तिब्बत समझौते' की 99 फीसदी बात तथ्यपरक और आधिकारिक है।

हालांकि मंगोलिया सरकार ने कहा कि वह किसी भी तरीके से इस संगोष्ठी में शामिल नहीं थी और न ही इसके बारे में उसने अपनी कोई राय प्रकट की।

लोकतांत्रिक चीन के लिए महासंघ के अध्यक्ष श्री क्विन जिन ने कहा, "हमारा मानना है कि परमपावन दलाई लामा से मिले समर्थन ने लिउ जियाबाओ को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सेरिंग वूएजर को पत्रकारिता में साहस का पुरस्कार

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 21 अक्टूबर)

बीजिंग में रहने वाली प्रख्यात तिब्बती लेखिका सुश्री सेरिंग वूएजर को इंटरनेशनल वूमेंस मीडिया फाउंडेशन द्वारा 19 अक्टूबर को करेज इन जर्नलिज्म (पत्रकारिता में साहस) पुरस्कार दिया गया। वूएजर ने साल 2008 में तिब्बतियों द्वारा चीन सरकार के विरोध में हुए प्रदर्शनों की खबर दी थी। इस पुरस्कार की घोषणा न्यूयॉर्क में की गई थी। इस पुरस्कार से सम्मानित तीन अन्य महिलाओं में कोलंबिया की क्लॉडिया जुलिएटा ड्यूक, मैक्सिको की अल्मा गुइलेरमॉप्रीएटो और तंजानिया की विकी टेटेमा शामिल हैं। इस पुरस्कार समारोह में करीब 600 लोग शामिल हुए, लेकिन इनमें वूएजर नहीं थीं क्योंकि चीन सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। हालांकि, वीडियो द्वारा भेजे अपने भाषण में उन्होंने बताया कि उन्होंने तिब्बतियों के विरोध प्रदर्शनों के तथ्य जुटाए और उसे अपने ब्लॉग 'इनविजिबल टिबेट' पर डाल दिया ताकि दुनिया यह जान सके कि तिब्बत में क्या हो रहा है। उनके ब्लॉग को हर दिन करीब 10 लाख लोग पढ़ते थे। चीन सरकार के

'मंगोलिया और तिब्बत के बीच 1913 का समझौता' विषय पर मंगोलिया के उलनबटार शहर में 13 से 14 अक्टूबर तक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आं

1. परमपावन दलाई लामा ने 1 अक्टूबर, 2010 को धर्मशाला में विधान प्रतिज्ञा क हुआ। फोटोः ओएचएचडीएल
2. धर्मशाला के गांगचेन किशांग के नागरिक रविवार, 3 अक्टूबर को प्राथमिक चुनावों
3. आमदो रेबकांग में एक रैली के दौरान तिब्बती विद्यार्थी। फोटोः एएफपी
4. धर्मशाला के तिब्बती चिल्ड्रेंस विलेज में 31 अक्टूबर को परमपावन दलाई लामा के
5. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कषति विभाग के कालोन –मंत्री– वेन सेरिंग फोटोः फायूल–नोर्बू वांग्याल
6. नेशनल कैम्पेन फॉर टिबेटन सपोर्ट, वर्धा के समर्थक रविवार, 17 अक्टूबर को वर्धा
7. तिब्बती राष्ट्रीय जनक्रांति के 51वें वर्षगांठ के अवसर पर अमेरिका में रहने वाले ति 'तिब्बत को आज़ाद करो–वर्ल्ड टुअर' की शुरुआत करते हुए।
8. मंगोलिया के उलनबटार में 13–14 अक्टूबर को 'मंगोलिया एवं तिब्बत के बीच 19
9. प्रतिनिधि थुबतेन सामदुप 29 सितंबर को पोलैंड के डांस्क में आयोजित 'युवा मंच' सॉलिडेरिटी सेंटर
10. सुश्री सेरिंग वूएजर 19 अक्टूबर को इंटरनेशनल वूमेंस मीडिया फाउंडेशन से करेज

(9)

(8)

(3)

(4)

ंख से तिब्बत

कराते हुए। इस प्रतिज्ञा में 46 ताइवानी, 16 तिब्बती और एक कोरियाई नागरिक शामिल

में वोट डालने के लिए झुंड में पहुंचे।

पहुंचने पर उनका स्वागत करते जेत्सुन पेमा। फोटोः तेनजिन छोजोर–ओएचएचडीएल
फुंसोक धर्मशाला में 27 अक्टूबर को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

से नागपुर की मोटरसाइकिल रैली के लिए तैयार होते हुए।
ब्बती प्रवासी लाकपा सेरिंग ने न्यूयॉर्क सिटी के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से 10 मार्च को

13 के समझौते' पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल लोग।
को संबोधित करते हुए। फोटोः लुकास्ज अंतरश्यूटज–अर्काइव ऑफ द यूरोपियन

न इन जर्नलिज्म अवॉर्ड हासिल करती हुई। फाइल फोटोः इपोक टाइम्स

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

(7)

(6)

अधिकारियों ने कई बार इस ब्लॉग को बाधित करने का प्रयास किया। वूएजर ने कहा, "तिब्बत में अब भी हर प्रकार की अमावनीय और अन्यायपूर्ण घटनाएं देखी जा सकती हैं। कई बेहतरीन लोगों, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अकल्पनीय यातना दी जाती है। मैं अपनी अकेले आधारित यह मीडिया अभियान जारी रखूंगी क्योंकि यह सत्ताहीन लोगों की हथियार है।"

तिब्बतियों के चुनावः निर्वासित तिब्बती ले रहे मतदान में हिस्सा

"हमारे पास कोई प्रशिक्षित तिब्बती कर्मचारी नहीं है। सारनाथ से आए लोग मानद सदस्य हैं और वे यहां हमेशा नहीं रहते। इतने बड़े पैमाने की परियोजना के लिए हमें विशेषज्ञों के लगातार सहयोग की जरूरत पड़ती है जो नहीं मिल पा रही है।"

(टिबेट डॉट नेट, 3 अक्टूबर, धर्मशाला)

निर्वासित तिब्बतियो की 15वीं संसद और तीसरे कालोन ट्रिपा (तिब्बती मंत्रिमंडल कशग के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री) के लिए जनता के द्वारा होने वाले आम चुनावों का प्रारंभिक दौर 3 अक्टूबर, रविवार को दुनिया भर के तिब्बती समुदाय में शुरू हो गया। साल 2006 के चुनावों के 72,771 मतदाताओं की तुलना में इस बार के चुनावों में 79,449 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अन्य दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले तिब्बती प्राथमिक चुनावों में अपना मत दे रहे हैं। भारत एवं नेपाल सहित अन्य देशों के जिन प्रमुख तिब्बती बस्तियों या देशों में मतदान चल रहा है उनमें धर्मशाला, बयालकुप्पी, मुंदगोड, हुनसुर, कोलेगल, भंडारा, मैनपाट, उड़ीसा, तेजू, मेओ, बोमडिला, लद्दाख, रवांगला, हर्बटपुर, दार्जिलिंग, देहरादून, मंडी, शिमला, दिल्ली, शिलांग, बंगलुरु, ताशीजोंग, बीर, सताउं, कमरो, पुरुवाला, बोंशी, कुल्लु, पोन्टा, डलहौजी, चाउंटरा, कालिमपोंग, वाराणसी, सारनाथ, काठमांडू, गांतोक, पोखरा, शा–वा–रासुम, नैनीताल, दीमापुर, लोसेरॉग, भूटान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, जापान, स्विटजरलैंड, बेल्जियम और रूस शामिल हैं।

धर्मशाला के 10 विभिन्न स्थानों पर बने मतदान केंद्र पर स्थानीय तिब्बती मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन केंद्र गांगचेन किशांग में बने मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें सड़क तक आ गईं थी और लोग धूप में लंबे समय तक धैर्य के साथ खड़े रहे। मतदान का अंतिम दौर 20 मार्च, 2011 को होगा।

पालि–संस्कृति–तिब्बती शब्दकोष का प्रकाशन

(टिबेट डॉट नेट, 6 अक्टूबर, धर्मशाला)

पुणे विश्वविद्यालय का पालि विभाग सारनाथ के केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पहली बार तीन भाषाओं पालि–संस्कृत–तिब्बती शब्दकोष का प्रकाशन करने जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पुणे विश्वविद्यालय के पालि विभाग के अध्यक्ष और इस परियोजना के संयोजक एम.ए. देवकर ने बताया, "इनमें से कोई सिर्फ एक भाषा जानने से बौद्ध अध्ययन समुचित रूप से नहीं किया जा सकता। आज ज्यादातर बौद्ध साहित्य तिब्बती या चीनी भाषा में है। एक ऐसे शब्दकोश की बेहद जरूरत है जो एक साथ इस्तेमाल हो सके–पालि को आधार बनाकर संस्कृत और तिब्बती भाषा को समानांतर रखा जाए। हम इसमें संदर्भ के लिए अंग्रेजी में भी अर्थ देंगे। इस परियोजना में भारतीय भाषाओं का काफी गहन अध्ययन करने की जरूरत होगी। इस परियोजना के आकार को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके लिए करीब 9 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया है। दृष्टि विकलांगता के शिकार देवकर ने बताया, आमतौर पर यूजीसी किसी परियोजना के लिए इतनी बड़ी राशि या कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं करता। लेकिन मेरा मामला विशेष है इसलिए उन्होंने मुझे दो अतिरिक्त सहायक मुहैया किया है। इसके अलावा मुझे सारनाथ के तिब्बती विश्वविद्यालय के दो सदस्यों का भी सहयोग मिल रहा है।" उन्होंने कहा, "हमारे पास कोई प्रशिक्षित तिब्बती कर्मचारी नहीं है। सारनाथ से आए लोग मानद सदस्य हैं और वे यहां हमेशा नहीं रहते। इतने बड़े पैमाने की परियोजना के लिए हमें विशेषज्ञों के लगातार सहयोग की जरूरत पड़ती है जो नहीं मिल पा रही है।"

इस परियोजना का करीब आधा काम पूरा हो चुका है और इससे जुड़े लोगों का दावा है कि यह परियोजना जून 2011 में पूरी हो जाएगी। देवकर ने कहा, "हम जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि हम तय समय तक इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम और समय मांगेंगे। हम इस शब्दकोश में चीनी भाषा को भी शामिल करना चाहते हैं क्योंकि कई बौद्ध साहित्य चीनी भाषा में भी हैं। पहले चरण में तो यह संभव नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।"

नेपाल में तिब्बतियों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांगी सहायता

(धर्मशाला, 11 अक्टूबर)

निर्वासित तिब्बती संसद ने संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल से इस बात के लिए मदद मांगी है कि नेपाल में रह रहे तिब्बती नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने चुनाव कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिया जाए। यह निवेदन उस घटना के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें नेपाल सरकार ने नेपाल में तिब्बतियों के आम चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डाली और 3 अक्टूबर को हो रहे पहले चरण के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदाता पेटियों को जब्त कर लिया गया। निर्वासित तिब्बती संसद की उपाध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नवंथेम पिल्लई और एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर को 8 अक्टूबर ऐसे निवेदन वाले पत्र लिखे। संसद की उपाध्यक्ष डोलमा ग्यारी ने इस पत्र में लिखा है, "मैं विनम्रता से यह बात बताना चाहती हूं कि 2 सितंबर, 2010 को निर्वासन में तिब्बती लोकतंत्र के 50

साल पूरे हुए हैं।

इस 3 अक्टूबर को निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोगों ने 15वें निर्वासित संसद और कालोन ट्रिपा के चुनाव के लिए प्राथमिक प्रक्रिया शुरू की। निर्वासित तिब्बती संसद के पहले चुने हुए सदस्यों ने 2 सितंबर, 1960 को कार्यभार ग्रहण किया था। पिछले 50 साल में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि हमारे समुदाय के लोगों द्वारा चुनाव के दिन कानून–व्यवस्था की कोई समस्या पैदा की गई हो। इसके अलावा हम अपने मेजबान देशों के प्रति इस बात के लिए कृतज्ञ रहे हैं कि उन्होंने कभी भी हमारे प्रतिनिधियों या कालोन ट्रिपा के चुनाव करने से हमें रोकने के लिए कोई व्यवधान नहीं डाला है। इसलिए नेपाल में हुई 3 अक्टूबर की घटना जिसमें स्थानीय सक्षम अधिकारियों द्वारा इजाजत देने के बावजूद नेपाली पुलिस कर्मी जबरन नेपाल की राजधानी काठमांडू के बौद्ध और स्वयंभू में बने मतदान केंद्रों से मतदान पेटियां जबरन उठा ले गए, बेहद सदमा पहुंचाने वाली बात है और लोकतंत्र के खिलाफ इस अभूतपूर्व कार्रवाई की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।" इस पत्र में कहा गया है, "निर्वासित तिब्बती संसद संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल से यह निवेदन करती है कि आप अपने अधिकारियों और व्यक्तिगत संपर्कों के द्वारा नेपाल पुलिस अधिकारियों से मतदान पेटियां वापस दिलाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि तिब्बती प्रवासी समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों और कालोन ट्रिपा का चुनाव कर सके।"

कनाडा की कंपनी द्वारा ग्यामा खदान के अधिग्रहण पर तिब्बतियों ने विरोध जताया

(फायूल डॉट कॉम, 18 अक्टूबर, धर्मशाला)

वैंकुवर के स्थानीय तिब्बती समुदाय के लोगों और उनके समर्थकों ने स्थानीय कंपनी चाइना गोल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज (सीजीजी) द्वारा तिब्बत में ग्यामा (चीनी भाषा में जियामा) खदान के अधिग्रहण के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन टर्मिनल सिटी क्लब के सामने किया गया जहां सीजीजी के शेयरधारक जियामा परियोजना की मालिक कंपनी स्काईलैंड माइनिंग के अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए एक बैठक में शामिल हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर और तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज थे और वे नारे लगाते हुए मांग कर रहे थे कि तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन बंद किया जाए। बैनरों पर लिखा हुआ था, 'चाइना गोल्ड, ह्यूमन राइट्स ऑन होल्ड' और 'चाइना गोल्ड, ह्यूमनिटी ऑन होल्ड'। ल्हासा नगर निगम के मेलड्रो गोंगकार काउंटी में स्थित ग्यामा खनन परियोजना तिब्बत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए चीन द्वारा चलाए जा रहे आठ प्राथमिकता वाली निर्माण परियोजनाओं में से एक है।

चीन की खनन कंपनी ने पिछले साल ऊपरी ग्यामा क्षेत्र में एक जल धारा मोड़ने की परियोजना को क्रियान्वित किया था जिसके तहत कृषि जमीन का जबरन अधिग्रहण किया गया था। करीब दो दशकों से ग्यामा की ऊपरी पहाड़ियों पर जारी खनन से ग्यामा शिंगछू नदी में बड़े पैमाने पर जहरीला कचरा डाला जा रहा है, जिससे पिछले साल वहां बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। इस घाटी में रहने वाले ग्रामीण अपने पेयजल और सिंचाई की जरूरतों के लिए ग्यामा शिंगछु पर ही निर्भर हैं। लेकिन भारी खनन से इसके संसाधनों के विनाश की वजह से नदी ही सूख गई है। सूत्रों के अनुसार इस इलाके के सभी प्राकृतिक झरने भी सूख गए हैं।

सीजीजी पर चीन की सरकारी कंपनी चाइना नेशनल गोल्ड ग्रुप का नियंत्रण है जिसकी ग्यामा खान में बहुल हिस्सेदारी है। विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि तिब्बत में बड़े पैमाने पर चल रहे खनन कार्यों से मानवाधिकारों, पर्यावरण विनाश एवं प्रदूषण, प्रॉपर्टी जब्त करने, जबरन विस्थापन, लोगों को जेल में डालने, प्रताड़ना और मौतों को बढ़ावा मिला है।

नाराज ग्रामीण 20 जून, 2009 को सड़कों पर उतर आए और चीनी खनन कर्मचारियों से भिड़ गए। नाराज तिब्बतियों और खनन कर्मचारियों के बीच हुई हाथापाई के बाद पुलिस ने धावा बोल दिया जिससे तीन तिब्बती नागरिक घायल हो गए। ग्यामा कस्बे में रहने वाले स्थानीय तिब्बती नागरिकों ने पिछले साल स्थानीय प्रशासन को एक याचिका देकर मांग की थी कि इस इलाके में चल रही खनन परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए।

हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस याचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया और समूचे इलाके में बड़ी संख्या में सेना के जवान तैनात कर दिए गए, बाहरी दुनिया से संपर्क और इस इलाके में बाहर से लोगों के आने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए।

ग्यामा खनन परियोजना फिलहाल चीन की सबसे बड़ी खनन परियोजना है जिसका संचालन तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के एक सरकारी उद्यम द्वारा किया जा रहा है। खबर मिली है कि इस परियोजना के पहले चरण के पूरा होने पर हर दिन यहां से करीब 6,000 टन उत्पादन होगा। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इस परियोजना में करीब 1.18 अरब डॉलर का भारी निवेश किया जा रहा है और इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यहां से हर दिन 15,000 टन उत्पादन हो सके।

तिब्बत में खनन लगातार एक विवादास्पद मसला बना हुआ है। तिब्बती लंबे समय से इस धारणा में विश्वास करते रहे हैं कि प्रकृति इतनी पवित्र चीज है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा खनन कंपनियां काम कर रही हैं जिससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि चीन और विदेश की कई कंपनियां तिब्बत की खराब राजनीतिक हालत का गलत फायदा उठाकर वहां के समृद्ध खनिज संसाधनों का दोहन करने में लगी हैं। उनका कहना है कि इस बारे में तिब्बती

नेपाल में हुई 3 अक्टूबर की घटना जिसमें स्थानीय सक्षम अधिकारियों द्वारा इजाजत देने के बावजूद नेपाली पुलिस कर्मी जबरन नेपाल की राजधानी काठमांडू के बौद्ध और स्वयंभू में बने मतदान केंद्रों से मतदान पेटियां जबरन उठा ले गए, बेहद सदमा पहुंचाने वाली बात है और लोकतंत्र के खिलाफ इस अभूतपूर्व कार्रवाई की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।"

नागरिकों से कोई मशविरा नहीं किया जाता है और इस मसले पर उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी जाती। मेलड्रो गोंगकार में स्थित ग्यामा शेन में ही तिब्बत के महान राजा सांगत्सेन गाम्पो (617 से 650 ईस्वी) का जन्म हुआ था। इस घाटी में करीब 15 गांव हैं जिसमें से दो में खानाबदोश लोग रहते हैं।

सीटीए और स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म ने मठों के प्रबंधन पर चीनी कानून को खारिज किया

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 27 अक्टूबर)

स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के धार्मिक और सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख चीनी सरकार द्वारा थोपे जा रहे कानूनों का तीव्र विरोध किया है, जिसका मकसद तिब्बत की पारंपरिक बौद्ध संस्कृति का अपमान करना है।

चीन जनवादी गणतंत्र के धार्मिक मामलों के प्रशासकीय विभाग, जिसने तथाकथित ''रेगुलेशन ऑन दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिबेटन बुद्धिस्ट मोनस्ट्रीज या आदेश संख्या 8'' जारी किया है, ने कहा है कि यह नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। धर्मशाला में गंछेन किशोंग में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री (सेरिंग फुंसोक) ने कहा कि नया कानून चीनी संविधान के प्रावधानों के एक दम उलट है, जिसमें कहा गया है कि ''चीन के नागरिकों को धार्मिक विश्वास अपनाने की आजादी है।''

चीनी संविधान का उद्धरण पेश करते हुए सेरिंग फुंत्सोक ने कहा कि कोई भी राज्य, संगठन या व्यक्ति किसी को भी कोई धर्म मानने या न मानने के लिए विवश नहीं कर सकता है, न ही वे किसी धर्म को मानने या न मानने वाले के साथ भेदभाव कर सकते हैं। राज्य साधारण धार्मिक गतिविधियों की रक्षा करता है। कोई धर्म का उपयोग ऐसी गतिविधियों में न करे, जिससे लोक व्यवस्था भंग होती है, नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है या जिससे राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में बाधा उपस्थित हो। धार्मिक संगठनों या धार्मिक गतिविधियों पर विदेशी नियंत्रण नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि चीनी संविधान के खिलाफ जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि चीनी नागरिकों को बिल्कुल भी धार्मिक आजादी नहीं है और इस देश पर व्यक्ति विशेष का शासन है, कानून का नहीं।

सेरिंग फुंत्सोक ने कहा कि तिब्बती बौद्ध विद्वान और धार्मिक प्रमुख आज तिब्बत से बाहर रह रहे हैं। इसलिए कहा जाना चाहिए कि पवित्र बौद्ध शिक्षा और गतिविधि निर्वासित तिब्बती समुदाय में मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि यह नियम चीन सरकार ने बौद्ध धर्म की पवित्र शिक्षा के तिब्बती क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए बनाया है। इसका मकसद बौद्ध मठों की धार्मिक गतिविधि के सामने कठिनाई पैदा करना है। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार इस कानून के सहारे तिब्बती बौद्ध परंपरा और अध्ययन को नष्ट करना चाहती है। वह बौद्ध मठों को जड़ से उखाड़ना चाहती है और शिक्षकों और छात्रों के बीच आध्यात्मिक रिश्ता कमजोर कर बौद्ध शिक्षा की जड़ खोदना चाहती है।

उन्होंने कहा कि इसलिए हम चीनी सरकार के इस प्रयास का जोरदार ढंग से विरोध करते हैं।

धर्मशाला में परमपावन के उपदेश सुनने 1300 से ज्यादा चीनी बौद्ध आए

(टिबेट डॉट नेट, धर्मशाला, 4 अक्टूबर)

57 देशों के करीब 5000 बौद्ध अनुयायी धर्मशाला के मुख्य मंदिर में परमपावन दलाई लामा के चार दिन के प्रवचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। इनमें ताइवान से आने वाले 1300 से ज्यादा चीनी बौद्ध अनुयायी भी शामिल हैं। परमपावन का प्रवचन सोमवार सुबह को शुरू हुआ और यह 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान परमपावन मध्यम मार्ग पर नागार्जुन के बुनियादी विवेक शोध (उमा सवे शेराब), अतिशा के प्रबोधन के लामा (जांगछुप लामड्रुन), सोंगखापा के 'आश्रित आरंभ की प्रशंसा में' (तेनड्रेल तोएपा) और सोंगखापा के 'प्रबोधन के मार्ग के लिए' संक्षिप्त चरण पर अपना प्रवचन देंगे। अपने उद्घाटन संबोधन में परमपावन ने इस बात पर अपने विचार रखे कि दूसरे लोगों के कल्याण के लिए किस प्रकार तीन नकारात्मक मानवीय कष्टों को दूर रखा जाए और सकारात्मक प्रेरणा कैसे उत्पन्न की जाए। पिछले शुक्रवार के दिन परमपावन ने विधान प्रतिज्ञा दिया। इस विधान प्रतिज्ञा समारोह में 46 ताइवानी, 16 तिब्बती और एक कोरियाई नागरिक ने हिस्सा लिया।

भारत लद्दाख के न्योमा को एयरबस के रूप में उन्नत करेगा

(टिबेटन रीव्यू डॉट नेट, 3 अक्टूबर, 2010)

चीन ने भारतीय सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है, उसने नए सैन्य साजोसामान तैनात किए हैं और तिब्बत सीमा पर बुनियादी ढांचा का तेजी से विकास कर रहा है। इससे भारत को भी जवाबी तैयारी करने को मजबूर होना पड़ा है। इसके तहत ही भारत ने न्योमा में मौजूद भारतीय वायु सेना के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) को उन्नत करने की तैयारी में है। भारतीय अखबारों में 1–2 अक्टूबर को यह खबर प्रकाशित की गई है। न्योमा की छोटी हवाई पट्टी के आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के 1 सितंबर को छपी खबर के अनुसार भारतीय वायु सेना के पश्चिमी एयर कमान के चीफ एयर मार्शल एनएके ब्रॉउन ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है। न्योमा चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 23 किलोमीटर दूर है।

प्रमुख आर्थिक अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के ऑनलाइन संस्करण में 2 अक्टूबर को छपा है कि न्योमा से वायु सेना के लड़ाकू विमान पास की उस सीमा पर अपनी हवाई कार्रवाई करने में सक्षम होंगे, जहां उन्हें 1962 में भारतीय सेना को चीनी सैनिकों के मुकाबले पीछे हटना पड़ा था क्योंकि उन्हें वायु सेना के लड़ाकू विमानों का साथ नहीं मिल पाया था।

ब्राउन ने कहा, "अगले तीन–चार साल में यह उन्नतीकरण होने के बाद हम न्योमा से वायु सेना का हर विमान उड़ा सकेंगे। हमारे आधुनिक लड़ाकू विमान खासकर सुखोई–30 एमकेआई ऐसे उंचे अक्षांश वाले हवाई अड्डों से संचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं।

साल 2008 में भारत ने यह तय किया था कि उत्तर भारत के चार वायु सेना केंद्रों तेजपुर, बागडोगरा, छाबुआ और हाशिमारा में सुखाई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान तैनात किए जाएं। यह सभी केंद्र चीन अधिकृत तिब्बत की सीमा से काफी करीब हैं। ब्राउन ने बताया कि भारतीय वायु सेना ने चीन द्वारा तिब्बत सीमा में किए जा रहे सभी तरह के विकास पर नजर रखा है।

उन्होंने कहा, "हम नए खतरों को देख रहे हैं और अपनी योजना बनाने में हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, चाहे वह चीन के नए बेस, सेंसर, मिसाइल, रडार और नए हथियार की बात हो। हम यह आकलन करेंगे कि इस सबका हम पर क्या असर पड़ सकता है।"

आज अगर गांधी जी होते तो क्या होता!

(डीपी न्यूज, न्यूजब्लेज, 6 अक्टूबर, धर्मशाला)

पूरे भारत के महात्मा गांधी के अनुयायी यह विश्लेषित करने के लिए जुटे कि आज की उस दुनिया में जो भौतिकवाद और लालच से भरी हुई है, गांधी के विचारों और मूल्यों की समीक्षा कैसे हो सकती है और उसे अपनाया कैसे जा सकता है। इस तीन दिवसीय शिविर का आयोजन महाराष्ट्र के ब्रहा विद्या मंदिर द्वारा महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज की शताब्दी के अवसर पर किया गया। महात्मा गांधी ने लंदन से लौटते समय किल्डोनॉन कास्टल जहाज पर यह पुस्तक लिखी थी। उनके अंदर किस तरह की भावना थी यह इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ 9 दिन में यह पुस्तक लिख डाली।

वह किताब लिखने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने दोनों हाथों से लिखना जारी रखा। जब दायां हाथ थक जाता तो वह बाएं हाथ से लिखने लगते। इस शिविर के दौरान हुए विचार–विमर्श का उद्देश्य गांधीवादी मूल्यों को मानवता के शोषण, हिंसा और लालच जैसे नकारात्मक प्रवृति के विकल्प के रूप में आगे बढ़ाना है। इस शिविर में देश के कई क्षेत्रों के गांधीवादी हस्तियों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कर्मचारियों सहित करीब 32 लोग शामिल हुए।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सामदोंग रिनपोछे ने गांधीवादियों के बीच संवाद और चर्चा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। रिनपोछे जी खुद प्रख्यात गांधीवादी हैं। कालोन ट्रिपा ने महात्मा गांधी के उन विचारों की चर्चा की जो उन्होंने हिंद स्वराज में बेहद संक्षिप्त, व्यापक और संघनित रूप में पेश किया है।

उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी तब लोग शायद उनके संदेश का सार ठीक से समझ नहीं पाए थे। आर्थिक समृद्धि हासिल करने के पागलपन की वजह से तेजी से औद्योगीकरण होने की वजह से बुनियादी जरूरतें हासिल करने की मानव की जरूरत ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की अतिलोभी इच्छा में बदल गई।

इसकी वजह से दुनिया पर अत्यधिक दबाव बन गया क्योंकि इस मानव लालच को पूरा करने के लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का ज्यादा से ज्यादा दोहन करने लगे। धन बनाने के पागलपन का असर चीन और रूस जैसे देशों में साफ तौर पर देखा गया है जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को अपनाया था और बाद में उन्होंने सरकार की पूंजीवादी व्यवस्था के सामने घुटने टेक दिए।

कालोन ट्रिपा ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा तिब्बत पर हमला पूंजीवाद और विस्तारवाद की नई विश्व व्यवस्था से प्रेरित था। कालोन ट्रिपा ने कहा, "एक ऐसे युग में जब अंधे भौतिकवाद आधारित वैश्वीकरण ने अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति साबित की है, असल शांति, सामंजस्य और समृद्धि गांधी जी के स्वराज की अवधारणा में निहित है। हिंद स्वराज का अध्ययन और मनन मानवता को पुनर्स्थापित करने के लिए जरूरी है।"

कालोन ट्रिपा ने बताया कि हिंद स्वराज में हमारे निजी और सामूहिक जीवन के सभी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं में सहजीवन संपर्कों के बारे में गहन दृष्टि और नैतिक जीवन व्यवस्था का दर्शन मिलता है।

कालोन ट्रिपा ने आखिर में कहा कि यदि मौजूदा पीढ़ी समृद्धि के लिए कुछ करना चाहती है तो हिंद स्वराज में दिए गए नैतिक और आत्म अनुशासन के मूल्य आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। शिविर में शामिल लोगों के अनुरोध पर कालोन ट्रिपा ने दोपहर के सत्र को तिब्बत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को समर्पित किया। उन्होंने धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बने तिब्बत और भारत के ऐतिहासिक रिश्तों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस शिविर के अगले सत्रों में गांधी के अनुयायी शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, सत्याग्रह, आधुनिक सभ्यता, धार्मिक सहिष्णुता गांधी जी के विचार और उनके अनुभवों पर प्रकाश डालेंगे।

प्रमुख आर्थिक अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के ऑनलाइन संस्करण में 2 अक्टूबर को छपा है कि न्योमा से वायु सेना के लड़ाकू विमान पास की उस सीमा पर अपनी हवाई कार्रवाई करने में सक्षम होंगे, जहां उन्हें 1962 में भारतीय सेना को चीनी सैनिकों के मुकाबले पीछे हटना पड़ा था क्योंकि उन्हें वायु सेना के लड़ाकू विमानों का साथ नहीं मिल पाया था।

तिब्बत सीमा पर स्थित नेपाली कस्बे में भारतीय राजदूत के दौरे में माओवादियों ने व्यवधान डाला

(आईएएनएस, काठमांडू, 6 अक्टूबर)

तिब्बत के सीमा पर स्थित नेपाल के सोलुखुंभू जिले के एक कस्बे में एक स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे भारत के राजदूत राकेश सूद के रास्ते में माओवाद सर्मथकों ने अड़चन डालने का प्रयास किया। इस परियोजना से सैकड़ों स्कूली बच्चों को फायदा होगा। यह क्षेत्र चीन के लिए संवदेनशील है क्योंकि उसे यहां से तिब्बत आंदोलन पनपने का डर है। माओवादी नेता और पूर्व संस्कृति मंत्री गोपाल किराटी के नेतृत्व में करीब तीन दर्जन लोगों ने उत्तरी नेपाल के फाफलू हवाई अड्डे पर राजदूत के पहुंचने पर काले झंडे दिखाए और भारत विरोधी नारे लगाए। यह वही माओवादी नेता हैं जिनके नेतृत्व में काठमांडू के पशुपतिनाथ में नियुक्त भारतीय पुजारियों पर हमला किया गया था। इसके पहले माओवादियों के एक स्थानीय संगठन शेरपा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेपाल ने बयान जारी कर भारतीय राजदूत से अपना दौरा रद्द करने की धमकी दी थी और कहा था कि ऐसा न करने पर उन्हें 'कड़े विरोध' का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले साल माओवादियों के हाथ से सत्ता जाने के बाद माओवादियों का चीन से रिश्ता और गहरा हो गया है। तो इस चेतावनी के पीछे भी चीन सरकार का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद साल 1950 में तिब्बतियों द्वारा की गई क्रांति के बाद से ही उत्तरी नेपाल का इलाका चीन के लिए काफी संवदेनशील रहा है और उसे लगातार यहां से आंदोलन शुरू होने का डर बना रहता है। चीनी कब्जे का विरोध करने वाले खामपा योद्धाओं ने उत्तरी नेपाल में अपना गुरिल्ला केंद्र बनाया था और उनको अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और भारत सरकार का भी सहयोग मिला था। माओवादियों के मोर्चे ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने उत्तरी नेपाल में फिर से चीन विरोधी आंदोलन को हवा देने के लिए 'तथाकथित सामाजिक एवं धार्मिक परियोजनाओं' को तेज कर दिया है। हालांकि, इस विरोध से अविचलित भारतीय राजदूत ने सेलारी में नेपाल–भारत मानव विकास की नई जिला शाखा का और लुकला में नेपाल नेत्र ज्योति संघ (एनएनजेएस) द्वारा आयोजित नेत्र शिविर का उद्घाटन किया। महेंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नेत्र शिविर में 800 से ज्यादा बच्चों के आंखों की जांच की गई। साल 2001 से ही नेपाल में एनएनजेएस द्वारा चलाए जा रहे नेत्र देखभाल कार्यक्रम को भारत सहयोग कर रहा है। भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग के इन कार्यक्रमों के तहत लोगों का मुफ्त में नेत्र जांच किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों के मोतियाबिंद और ट्रकोमा का इलाज किया गया है और 18,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को चश्मा दिया गया है। भारतीय राजदूत सूद का स्कूल में पहुंचने पर बच्चों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया जो सड़के किनारे पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। भारतीय राजूदत का माओवादियों को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। स्थानीय नेताओं ने उन्हें एक प्रस्ताव देकर मांग की कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 12 अन्य परियोजनाएं शुरू की जाएं।

"तिब्बतियों की तरफ से निर्वासित तिब्बती संसद लिउ को हार्दिक बधाई देती है। यह चीन में लोकतंत्र के विकास और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए एक नया अध्याय है। हमें उम्मीद है कि लिउ 10 दिसंबर को ओस्लो में होने वाले सम्मान समारोह में शामिल हो सकेंगे।"

लिउ को नोबेल मिलने से चीन में आ सकता है बदलाव

(आईएएनएस, धर्मशाला, 12 अक्टूबर)

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा है कि जेल में बंद सरकार विरोधी नेता लिउ जियाबाओ को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से चीन में बदलाव की बयार बह सकती है।

खुद नोबेल शांति पुरस्कार हासिल कर चुके आध्यात्मिक नेता ने जापान में सोमवार को कहा, "चीन में बदलाव कई कारकों पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से इस नोबेल शांति पुरस्कार को ऐसा ही एक कारक माना जा सकता है। चीन में बदलाव लाने के लिए कई लिउ जियाबाओ की जरूरत है।" केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट पर जारी एक खबर में यह जानकारी दी गई है। नार्वे की नोबेल समिति ने ओस्लो में 8 अक्टूबर को घोषित किया था कि चीन में राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित करने के आरोप में 11 साल की सजा भुगत रहे लिउ को चीन में मानवाधिकारों की लंबी लड़ाई के लिए इस पुरस्कार के लिए एकमत से चुना गया। इस पर 75 साल के दलाई लामा ने कहा, "चीनी नेताओं को अब अपने दिमाग की खिड़की खोलनी चाहिए और संकीर्ण सोच वाले रवैए से बाहर निकलना चाहिए। वहां के नेताओं को इस सचाई को स्वीकार करना चाहिए कि चीनी लोग जो मांग कर रहे हैं वह वहां के संविधान में पहले से ही दिया गया है। बीबीसी, सीएनएन और अन्य समाचार माध्यमों पर रोक लगाने से कोई मदद नहीं मिल सकती। इससे केवल चीन की बदनामी ही होती है।" चीन में लोकतंत्र लाने की दिशा में लिउ के योगदान की चर्चा करते हुए आध्यात्मिक नेता ने कहा, "आपके इस महान प्रयास को दुनिया ने पहचाना है और इस अस्थायी गतिरोध के बावजूद आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने नैतिक ताकत और दृढ़ता को बनाए रखें। दुनिया आपके साथ है।"

पहाड़ी शहर धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती संसद ने भी मंगलवार को लिउ को बधाई दी। संसद ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "तिब्बतियों की तरफ से निर्वासित तिब्बती संसद लिउ को हार्दिक बधाई देती है। यह चीन में लोकतंत्र के विकास और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए एक नया अध्याय है। हमें उम्मीद है कि लिउ 10 दिसंबर को ओस्लो में होने वाले सम्मान समारोह में शामिल हो सकेंगे।" दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब चीनी सेनाओं ने ल्हासा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तब

दलाई लामा ने अपने कई समर्थकों के साथ 1959 में भारत में शरण ले लिया। तब से यहां वहां तिब्बतियों के निर्वासित तिब्बती सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।

रेल संपर्क के द्वारा भारत के दरवाजे तक पहुंचेगा चीन

(जी न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली, 14 अक्टूबर)

चीन ने पिछले महीने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल संपर्क क्विंघई–तिब्बत रेलवे को तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगास्ते तक ले जाने का काम शुरू किया है। चीन के इस कदम से भारत में बेचैनी महसूस की जा रही है क्योंकि अब चीन का रेल संपर्क नेपाल की सीमा के पास तक हो जाएगा। एक प्रमुख समाचार पत्र के अनुसार चीन सरकार धीरे–धीरे रेल संपर्क को यांगत्री तक ले जाने की योजना पर भी काम कर रही है जो अरुणाचल प्रदेश से सटे चीनी सीमा में स्थित है। चीन अरुणाचल पर लंबे समय से अपना दावा कर रहा है। अरुणाचल के कुछ इलाकों को यांगत्री या निंगची प्रशासन का हिस्सा बताने वाले चीनी ब्रह्मपुत्र की धारा को उत्तर की ओर मोड़ने के अलावा यहां दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी बनाने की योजना बना रहे हैं। योजना के अनुसार चीन ल्हासा से दक्षिण–पश्चिम में तिब्बत–नेपाल सीमा के पास स्थित शिगास्ते तक रेलमार्ग ले जाएगा और यांगत्री तक के रेल लाइन को आगे बढ़ाकर दक्षिण–पूर्व में अरुणाचल की ओर ले जाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार खासकर अरुणाचल की सीमा तक बनने वाले रेल संपर्क को लेकर परेशान क्यों है। इसकी वजह यह है कि चीन ने इस साल पहली बार रेल संपर्क के द्वारा लड़ाकू विमानों की तैयारी से जुड़ी सामग्री तिब्बत क्षेत्र तैनात चीनी वायु सेना तक पहुंचाया है। पीएलए डेली के अनुसार चीन ने तिब्बत में अपना पहला बड़ा पैराशूट अभ्यास किया है ताकि अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन कर सके कि वह दुनिया की इस सबसे उंचे पठार पर तेजी से सेनाओं को भेज सकता है।

वर्धा के तिब्बत समर्थकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली

(वर्धा, 19 अक्टूबर)

तिब्बतियों के समर्थन के लिए राष्ट्रीय अभियान, वर्धा द्वारा तिब्बत आंदोलन के प्रति समर्थन जताने के लिए एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार 100 से ज्यादा समर्थकों ने महाराष्ट्र के वर्धा से नागपुर की यात्रा शुरू की। इस रैली को हरी झंडी वर्धा के विधायक प्रोफेसर सुरेश देशमुख ने दिखाई। इस बाइक रैली का संदेश था, 'तिब्बत को आज़ाद करो, भारत को बचाओ'। इस रैली का आयोजन दशहरे के दौरान किया गया और संयोग से इसी दिन बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा नागपुर की दीक्षाभूमि में शुरू किए गए धर्मचक्र दिवस की 54वीं वर्षगांठ थी। गौरतलब है कि पूरे भारत से 15 लाख से ज्यादा अम्बेडकर समर्थक दशहरे के दिन दीक्षाभूमि में इकट्ठा होते हैं। इस बार यह आयोजन 16 से 18 अक्टूबर तक तीन दिन के लिए चला। रैली में शामिल मोटरसाइकिल सवारों का नागपुर पहुंचने पर स्वागत क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ द्वारा किया गया। तिब्बती नॉर्गेलिंग बस्ती के लोगों ने कथक के साथ मोटरसाइकिल सवारों का स्वागत किया। बाद में दीक्षाभूमि जाकर यह रैली समाप्त हुई। दीक्षाभूमि में तिब्बत आंदोलन के लिए राष्ट्रीय अभियान द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में तिब्बत से संबंधित हजारों पत्रक बांटे गए। जनसमूह को पत्रक वितरण के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय युवा कांग्रेस, क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ, नॉर्गेलिंग बस्ती, भारत–तिब्बत मैत्री समाज की नागपुर शाखा और भारत–तिब्बत मैत्री समाज की भंडारा शाखा के सदस्यों ने भी सहयोग किया। वर्धा में एक तिब्बत समर्थक समूह तिब्बत आंदोलन के लिए राष्ट्रीय अभियान के द्वारा यह लगातार तीसरे साल आयोजित की गई मोटरसाइकिल रैली थी।

50 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार100 से ज्यादा समर्थकों ने महाराष्ट्र के वर्धा से नागपुर की यात्रा शुरू की। इस रैली का संदेश था, 'तिब्बत को आज़ाद करो, भारत को बचाओ'।

भारत के लिए क्षोभजनक हैं चीन एवं पाकिस्तानः भारतीय सेना प्रमुख

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 19 अक्टूबर)

भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन एवं पाकिस्तान भारत के लिए क्षोभजनक हैं। थल सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी सीमा के समानांतर मौजूद आतंकी ढांचा और चीन की बढ़ती सैन्य कारगुजारी भारत के लिए चिंता का विषय हैं। यहां 'भारतीय सेनाः उभरती भूमिका एवं लक्ष्य' विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए जनरल सिंह ने कहा, 'हमारे लिए दो क्षोभ के बिंदु हैं। पहला, पाकिस्तान में हालात किस तरह के हालात हो गए हैं, वहां सरकार चलाने की समस्या है, वहां आतंकवादियों को कुछ हद तक समर्थन हासिल है और वहां के आंतरिक हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात का परिणाम इस लिहाज से देखना होगा कि वहां की चीजें यहां किस तरह से असर डालती हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत के लिए तब तक कुछ चिंता करने की बात है जब तक सीमा के दूसरे तरफ आतंकी ढांचा सुरक्षित बना रहता है। इसी प्रकार हमारे एक तरफ आर्थिक और सैन्य, दोनों लिहाज से उभरता हुआ चीन है। हमारे बीच विश्वास बहाली के उपाय हुए हैं, हमारी सीमा की हालत काफी स्थिर है, फिर भी हमारे बीच सीमा विवाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या चीन के साथ परंपरागत युद्ध की संभावना तो काफी अनिश्चित बात है, लेकिन झड़पें जरूर हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम परंपरागत हमले से निबट सकें और परमाणु हमले के लिए भी तैयार रहें।"

योजना के अनुसार चीन ल्हासा से दक्षिण–पश्चिम में तिब्बत –नेपाल सीमा के पास स्थित शिगास्ते तक रेलमार्ग ले जाएगा और यांगत्री तक के रेल लाइन को आगे बढ़ाकर दक्षिण–पूर्व में अरुणाचल की ओर ले जाया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने जामिया द्वारा दलाई लामा को सम्मानित करने पर आपत्ति जताई

(द टिबेट पोस्ट डॉट कॉम, धर्मशाला, 23 अक्टूबर)

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी द्वारा दलाई लामा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करने की योजना पर भारत सरकार ने गंभीर आपत्ति जताई है।

जामिया का दलाई लामा को 23 नवंबर को सम्मानित करने का कार्यक्रम था। मीडिया में छपी खबर में बताया गया कि विदेश मंत्रालय जामिया की योजना पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जामिया की मीडिया कोऑर्डिनेटर सीमा मल्होत्रा ने कहा कि उप कुलपति ने विदेश सचिव से बात की है और विश्वविद्यालय ने भी एक पत्र देकर मंत्रालय से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

विदेश सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि दलाई लामा अत्यधिक सम्माननीय धार्मिक और आध्यात्मिक नेता हैं इसलिए मंत्रालय इस मसले पर संवेदनशील है।

दलाई लामा को सम्मानित करने की योजना ऐसे समय में आई है, जब भारत और चीन का रिश्ता तनावपूर्ण है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अक्टूबर अंत में भारत–आसियान सम्मेलन में चीनी समकक्ष से अनौपचारिक मुलाकात का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि भारत–चीन संबंध की मौजूदा स्थिति के कारण विदेश मंत्रालय इस मामले में सतर्क है। पिछले साल चीन ने दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर आपत्ति जताई थी। इस प्रदेश को वह चीन का क्षेत्र मानता है। इधर भारत ने ले. जनरल बी.एस. जसवाल को चीन का वीजा न दिए जाने पर विरोध जताया था। सिंह और दलाई लामा की मुलाकात के बाद बीजिंग ने इस मसले पर तीव्र विरोध जताया था। चीन ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को पासपोर्ट के साथ एक अलग कागज पर नत्थी कर वीजा देना शुरु कर जम्मू और कश्मीर पर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया था।

पिछले दिनों राव ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश में कहा कि दोनों देशों के बीच मिलकर आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हैं।

जामिया के मसले पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जब जामिया का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय को भेजा, तो विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया थी कि दलाई लामा को इस समय सम्मानित करना उचित नहीं होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय के फैसले ने विश्वविद्यालय को निराश किया है। विश्वविद्यालय प्रांगण में दलाई लामा की मौजूदगी का छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। विदेश सचिव से मिलने के बाद उप कुलपति जंग ने कहा कि राव ने इस मुद्दे पर फिर से सोचने का भरोसा दिलाया है। दलाई लामा को दुनियाभर में इस तरह का सम्मान मिल चुका है, पर जामिया उन्हें सम्मानित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय होता।

यहां तक कि कश्मीर के अक्साई चिन को भी चीन के उत्तर –पश्चिमी हिस्से के तौर पर दिखाया गया है।चीन की नयी ऑनलाइन मैपिंग सेवा बहुत कुछ गूगल अर्थ और गूगल मैपिंग की तरह का है, जिसमें वास्तविक और उपग्रहीय मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है। मैप वर्ल्ड सेवा चीनी भाषा में उपलब्ध है।

चीन के मैप वर्ल्ड ने अरुणाचल को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया

(सिलिकॉनइंडिया डॉट कॉम, बीजिंग, 25 अक्टूबर)

चीन लगातार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताता रहा है। इसी की अगली कड़ी में चीन की ऑनलाइन मानचित्र सेवा 'मैप वर्ल्ड' ने अरुणाचल प्रदेश को चीनी हिस्सा के तौर पर दिखाया है। चीन ने गूगल अर्थ से मुकाबला करने के लिए मैप वर्ल्ड सेवा शुरू की है। मैप वर्ल्ड में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन में तिब्बत के दक्षिणी हिस्से के तौर पर पेश किया गया है और भारतीय सीमा को दक्षिण की ओर असम सीमा पर खिसका कर दिखाया गया है। यहां तक कि कश्मीर के अक्साई चिन को भी चीन के उत्तर–पश्चिमी हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। चीन की नयी ऑनलाइन मैपिंग सेवा बहुत कुछ गूगल अर्थ और गूगल मैपिंग की तरह का है, जिसमें वास्तविक और उपग्रहीय मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है। मैप वर्ल्ड सेवा चीनी भाषा में उपलब्ध है।

इसे चीन के निरंतर अरुणाचल प्रदेश को चीनी हिस्से बताने के प्रचार के तौर पर देखा जा रहा हैं पहल भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीनी वीजा कई बार देने से इंकार किया है। चीन कहता रहा है कि वे लोग चीनी नागरिक हैं, उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। हाल में एप्पल के आईफोन 4 में भी अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। मैप वर्ल्ड सेवा के बारे में स्टेट ब्यूरो ऑफ सर्वेइंग एंड मैपिंग (एसबीएसएम) के उपनिदेशक मिन यिरेन ने कहा कि नक्शे के बारे में सभी सूचनाएं एसबीएसएम और संबंधित दशों के सुरक्षा विभागों की अनुमति से डाली गई हैं। अप्रमाणित नक्शों को देश ने फायरवाल कर दिया है। सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन मैपिंग सेवा देने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की जरूरत होती है। इन कम्पनियों को नक्शों से संबंधित आंकड़ों को जमा करने के लिए चीन में सर्वर रखना जरूरी है। जानकारी मिली है कि ऑनलाइन मैपिंग सेवा पर पिछले दो सालों से काम चल रहा है। यह साइट दो सालों में एक बार अपडेट होगा। जबकि गूगल अर्थ में हर दो मिनट पर उपग्रह से डाटा अपलोड होता है। गूगल अर्थ से यह साइट चाहे मुकाबला कर पाए या नहीं, लेकिन समय के साथ इस साइट को तो लोग जानने ही लगेंगे। लेकिन भारतीयों के लिए वास्तविक चिंता तो यह है कि आखिर चीन भारत के एक हिस्से को अपना बताना कब बंद करेगा?